योजना के अंतर्गत हाल ही में सुपर बाजार की शाखाओं का वर्गीकरण किया गया है,

(ख) यदि हां,तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस नई योजना की क्या विशेषतांए हैं,

(ग) क्या नई योजना को शुरू किये जाने के परिणामस्वरूप सुपर बाजार के अनेक बिक्री सहायक बेरोजगार हो जायेंगे,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ड.) इन बिक्री सहायकों को उपयुक्त रूप से पुनर्नियोजित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) से (ड.) प्रश्न नहीं उठता है।

मध्य प्रदेश में स्थापित किये गये वनस्पति तेल संयंत्रों की संख्या

1144. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए वनस्पति तेल संयंत्रों की जिला-वार संख्या कितनी है,

(ख) इन संयंत्रों का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में राज्य में ऐसे और अधिक संयंत्र स्थापित करने का विचार रखती है,

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या-क्या है जहां पर ये संयंत्र स्थापित किए जांएगे और क्या इनमें से कुछ संयंत्र आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने की भी संभावना है, और

(ड.) सरकार द्वारा इन संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) वनस्पति तेल उद्योग के 25 जुलाई, 1991 से लाइसेंस मुक्त कर दिए जाने क परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश में इस समय वनस्पति तेल संयंत्रों की संख्या के बारे में कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है । साल्वेट निष्कर्षण संयंत्रों तथा वनस्पति संयंत्रों, जो कि विलायक निष्कर्षित तेल, विवैलित चूर्ण तथा खाद्य चूर्ण नियंत्रण आदेश, 1967 तथा वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) ओदश, 1947 के तहत आते हैं, के संबंध में सूचना उपबंध हैं । एक विवरण (नीचे देखिए) दिया गया है । जिसमें, मध्य प्रदेश में इन संयंत्रों की जिलावार संख्या दी गई है।

(ख) मध्य प्रदेश में वनस्पति का वार्षिक उत्पादन लगभग 0.75 लाख मी.टन है। मध्य प्रदेश में तिलहन उत्पादन के आधार पर वनस्पति तेलों का वार्षिक उत्पादन 9 लाख मी.टन के आस-पास आंका गया है ।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ड.) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मध्य प्रदेश में जिलावार साल्वेट निष्कर्षण संयंत्रों/वनस्पति संयंत्रों की जिलावार संख्या का विवरण ।

क्रम सं.	जिला	साल्वेट निष्कर्षण संयंत्रों की संख्या	वनस्पति संयंत्रों की संख्या
1.	बालाघाटा	2	-
2.	भोपाल	4	-
3.	बिलासपुर	3	-
4.	छिन्दवाड़ा	5	-
5.	देवास	11	-
6.	दुर्ग	1	-
7.	धार	5	1
8.	दामोह	1	-
9.	जगदलपुर	1	-
10.	होशंगाबाद	6	-
11.	इन्दौर	14	2
12.	खरगांव	3	-
13.	खण्डवा	4	1
14.	माण्डला	1	-
15.	मुरेना	1	-
16.	नरसिंहपुर	1	-
17.	रायगढ़	2	-
18.	रायपुर	9	-
19.	रायसेन	4	1
20.	रतलाम	5	-

क्रम सं.	जिला	साल्वेट निष्कर्षण संयंत्रों की संख्या	वनस्पति संयंत्रों की संख्या
21.	राजनांदगांव	2	-
22.	शाजापुर	6	-
23.	सीहोर	2	-
24.	सेवनी	1	1
25.	दतिया	1	-
26.	सीधी	-	1
27.	टीकमगढ़	1	-
28.	उज्जैन	3	-
29.	विदिशा	2	-
	योग	101	7

Formation of committee to study employment iti semi-skilled sector

1145. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is it fact that trade unions have requested the formation of a committee to study the level of employ ment in various semi-skilled sectors;

(b) it so, the details of such representations; and

(c) the steps Government propose to take for monitoring employment levels in semiskilled sectors?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) Suggestions have been received from various trade unions to conduct studies to ascertain the status of employment in India as a result of restructuring and liberalisation of the economy. However, no formal request has been received from the trade unions for setting up a committee to study the level of employment in various semiskilled sectors.

(c) Expansion of employment opportunities has been an important objective of development planning including the 8th Five Year Plan. In order to achieve the targcttcd growth of employment. Government is constantly monitoring the employment level in various sectors of the economy.

Allocation of funds for Rural Employment and Development

1146. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the funds allocated for the Rural Employment and Rural Development during last year in the country, Statewise;

(b) the funds utilised during last year;

(c) the details thereof State-wise; and

(d) whether Government are checking the progress of the implementation thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) to (c) The allocation and utilisation of funds under major rural employment and rural development programmes in the country (State-wise) during the last year is given in the appended statement. *[See appendix 176, Annexure No 46]*

(d) All efforts arc being made to ensure proper implementation of various programme's in accordance with the guidelines issued. Further an effective system for monitoring the implementation of programmes has also been evolved through (a) periodical progress reports: (b) review meetings/workshops of project Directors of DRDA; (c) review meeting of Secretaries/Commissioners incharge of rural development of States; (d) meetings of State Level Coordination Committees; (e) field inspections by Senior Officers from the Centre under the Area Officer Scheme; and (f) Concurrent Evaluation of programmes. In addition the Department of Programme Implementation also monitors the progress of the major rural